Title: Urged upon the Government to amend the Land Acquisition Act so that payment is made according to the market rate by the Central or State Governments while acquiring land from the farmers.

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नेशनल कैपिटल टैरिटरी जो दिल्ली है, उसके तीन तरफ हरियाणा प्रदेश लगता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रीज को दिल्ली से बाहर निकालने का जो आदेश दिया था, उससे दिल्ली की सभी फैक्ट्रियां पड़ोसी प्रान्तों में जा रही हैं।

15.00 hours (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए)

हरियाणा चूंकि दिल्ली से लगता है इसलिए अधिकतर इंड्स्ट्रीज हरियाणा में जा रही हैं। जो भी प्रदेश दिल्ली के साथ लगते हैं चाहे वह राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, वहां की सरकारें धड़ाधड़ किसानों की जमीन एक्वायर कर रही हैं। जो छोटे-छोटे किसान हैं और जिन के पास एक-दो एकड़ जमीन है, उनकी जमीन एक्वायर हो रही है। सभापति महोदय, आप स्वयं भी किसान हैं। किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव एक्वायर हो रही हैं और करोड़ों रुपए एकड़ के हिसाब से बेची जा रही है। राज्य सरकारों ने इसे व्यापार बना लिया है। आज किसान मर रहा है। आप दिल्ली के बॉर्डर के किसी साइड में चले जाएं आपको ये सब देखने को मिलेगा। किसानों की जमीन हरियाणा में एक्वायर हो रही है। बॉर्डर पर किसानों से जमीन एक लाख 90 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से ली जा रही है और उसे पांच-पांच हजार रुपए गज में बेचा जा रहा है।

लेकिन हरियाणा बार्डर से जो जमीन दिल्ली में लगती है, दिल्ली सरकार उस जमीन का किसानों को 23 लाख रुप्ये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा देती है। बार्डर से इधर हरियाणा में लगती जमीन 1 लाख 90 हजार रुप्ये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानो से एक्वायर कर रही है। इस तरह एक-एक और दो-दो एकड़ जमीन रखने वाला किसान बर्बाद हो रहा है। इससे किसानों मे भय पैदा हो गया है। वे दुखी हैं तथा बेघर हो गये हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि लैंड एक्वीज़ीशन एक्ट में संशोधन करना चाहिये जिसके अंतर्गत, यदि केन्द्र या राज्य सरकार किसानों की जमीन अधिग्रहण करे तो उसे मार्किट रेट पर पैसा दिया जाना चाहिये। ऐसा देखा गया है कि राज्य सरकारों ने इस प्रकार की दुकानदारी बना ली है कि किसानों से सस्ते रेट पर जमीन लेकर महंगे रेट पर बेच रही है। सरकार को इस बात का नोटिस लेना चाहिये।